PRGI. No.: MHMUL/25/A2419

प्यूपिल्स टाइम्स

PUPILS TIMES

Volume : 1 ▸ Issue : 29 ▸ Mumbai ▸ Friday, 21 August to 27 August 2026 ▸ Weekly ▸ Pages : 8 ▸ Price : 3 Rs.

राष्ट्रपति मुर्मु का आईआईएस अधिकारियों को संदेश

'सोशल मीडिया का इस्तेमाल लोगों की चिंताएं सुनने के लिए करें'

नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस (आइआइएस) अधिकारियों के एक समूह से कहा कि वे इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी देने और लोगों से जुड़ने के लिए ही नहीं, बल्कि लोगों की चिंताओं को सुनने और उन पर प्रतिक्रिया देने के लिए भी करें। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया ने नागरिकों के जानकारी पाने, उसे साझा करने और उस पर प्रतिक्रिया देने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। राष्ट्रपति ने यह बातें इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के ट्रेनी अधिकारियों से कही। ये अधिकारी राष्ट्रपति भवन में उनसे मिलने आए थे। उन्होंने कहा कि ये अधिकारी यह सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाएंगे कि सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों और पहलों की जानकारी लोगों तक साफ-साफ, सही-सही और समय पर पहुंचे। राष्ट्रपति ने कहा कि जानकारी के तेजी से जटिल होते माहौल में उन्हें सही तथ्यों और गलत सूचनाओं के बीच फर्क करना होगा। संकट के समय आपको जिम्मेदारी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए।

ऐसे समय में, जब गलत सूचनाएं बहुत तेजी से फैलती हैं, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नागरिकों को सही और विश्वसनीय जानकारी आसानी से और समय पर मिले।

पीएम मोदी की मुफ्त कोचिंग पहल के क्रियान्वयन को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक की

नई दिल्ली: केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बुधवार को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल के क्रियान्वयन को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में इस पहल की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री जोशी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर कहा कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ हुई बैठक का मुख्य मकसद 'एक मजबूत राष्ट्रीय मंच बनाना था, जिससे देश भर के छात्रों को उच्च-गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री, विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और व्यवस्थित तैयारी की सुविधा मिल सके'। प्रधानमंत्री ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के परिवारों पर आर्थिक बोझ कम करने के लिए मुफ़्त ऑनलाइन कोचिंग की घोषणा की थी। पीएम मोदी ने 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा था, 'कोचिंग कक्षाएं गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों पर बोझ हैं। हम विभिन्न परीक्षाओं के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग उपलब्ध कराएंगे।' उन्होंने कहा था, "हर माता-पिता को लगता है कि अगर वे अपने बच्चे को कोचिंग कक्षा में नहीं भेजते हैं तो उनका परिवार प्रतिष्ठित नहीं माना जाएगा।" पीएम- मोदी ने 15 अगस्त 2026 को अपने 80वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में गरीब और मध्यमवर्गीय विद्यार्थियों के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग पहल की घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य महंगे कोचिंग संस्थानों के आर्थिक बोझ को कम करना और दूरदराज के ग्रामीण छात्रों को डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है।

भारत और जापान के बीच

रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न

नई दिल्ली: भारत और जापान के बीच रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी ने बैठक की सह-अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, 'मेक इन इंडिया' के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमी और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोटो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की। सिंह ने कहा कि भारत को भूकंप के कारण हुई जनहानि पर गहरा दुख है। उन्होंने इस मुश्किल समय में हर जरूरी सहायता, राहत और सहयोग देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत-जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और लंबे समय से चले आ रहे सभ्यतागत संबंधों पर आधारित हैं। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे करेंगे। सिंह ने कहा कि वर्षों के दौरान यह मित्रता दोनों देशों के साथ-साथ पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता, मजबूती और नियम आधारित व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बन गई है।

(शेष पेज 5 पर)

भारत की विकास यात्रा में राजीव गांधी का भी अहम योगदान: राजनाथ सिंह

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती की अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बड़ा बयान दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में राजीव गांधी का भी अहम योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत की विकास यात्रा में उनका भी अहम योगदान रहा है। पूर्व पीएम राजीव गांधी की भूमिका भारत को आधुनिक, समृद्ध और सशक्त राष्ट्र बनाने में अहम रही। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को विश्व में वर्तमान स्थान दिलाया और इसीलिए उन्हें भारत में 'सूचना प्रौद्योगिकी का जनक' कहा जाता है। उन्होंने देश में कंप्यूटर और आधुनिक तकनीक के उपयोग की शुरूआत की थी। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हर साल 'सद्भावना दिवस' के रूप में मनाया जाता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने राजीव गांधी की समाधि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने भारत के निर्माण और तरक्की के लिए आधुनिक तकनीक और नए विचारों को अपनाने में विश्वास जताया।

भारत अगले वर्ष तटरक्षक बल के 5वें वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा

नई दिल्ली: भारत अगले वर्ष फरवरी में नई दिल्ली में तटरक्षक बल के पांचवें वैश्विक शिखर सम्मेलन (सीजीजीएस) की मेजबानी करेगा। ये आयोजन भारतीय तटरक्षक बल की स्वर्ण जयंती के अवसर पर होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह शिखर सम्मेलन भारत के महासागर दृष्टिकोण और सहयोगात्मक तथा प्रगतिशील समुद्री व्यवस्था के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण उदाहरण होगा। रक्षा मंत्रालय के अनुसार यह आयोजन अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग को मजबूत करने और सुरक्षित, स्वच्छ तथा अधिक सुरक्षित समुद्रों की दिशा में सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की भी पुष्टि करता है। इस ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों के तहत, भारतीय तटरक्षक बल ने हाइब्रिड मोड में पांचवें सीजीजीएस की कार्यकारी स्तरीय बैठक की मेजबानी की। इस बैठक में तटरक्षक बल और समुद्री एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय और क्षेत्रीय समुद्री संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। मंत्रालय ने कहा कि इस बैठक ने सीजीजीएस के लिए तैयारियों को आगे बढ़ाने और सहभागी समुद्री एजेंसियों के बीच संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच परियोजनाओं को दी मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनमें चार रेलवे परियोजनाएं और एक राजमार्ग परियोजना शामिल हैं। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 13 हजार 41 करोड़ रुपये की इन परियोजनाओं को मंजूरी दी। वैष्णव ने बताया कि रेलवे की चार मल्टीट्रैकिंग परियोजनाएं पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों को सेवाओं के दायरे में लाएंगी। ये परियोजनाएं हैं खड़गपुर भद्रक चौथी लाइन, भद्रक-हरिदासपुर चौथी लाइन, गुम्मिडीपुंडी-गुदुर तीसरी और चौथी लाइन और कटक-पारादीप तीसरी और चौथी लाइन। इससे भारतीय रेलवे नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9 हजार 450 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है। वैष्णव ने कहा कि विस्तारित रेल लाइन से आवागमन में काफी सुधार होगा। इससे भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में भी वृद्धि होगी। प्रस्तावित मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं से लगभग 60 लाख की आबादी वाले लगभग 6 हजार 448 गांवों तक पहुंच बढ़ेगी। प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल संपर्क में सुधार होगा। इनमें कुलदिहा वन्यजीव अभ्यारण्य, भीतर्कनिका राष्ट्रीय उद्यान, मां भद्रकाली मंदिर, मां धमराई मंदिर, पंचलिंगेश्वर मंदिर, पुलिकट झील, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, भगवान वीरराघव पेरुमल मंदिर, धबलेश्वर मंदिर और बौद्ध स्थल ललितगिरि शामिल हैं। (शेष पेज 5 पर)

संपादकीय

'वंदे मातरम' पर विवाद

स्वतंत्रता दिवस समारोह पर अपने मुख्यालय में संपूर्ण वंदे मातरम के गायन को लेकर जो विवाद पैदा हुआ, उसके लिए कांग्रेस अपने अलावा अन्य किसी को दोष नहीं दे सकती। कांग्रेस कुछ भी सफाई दे, यह मानने के अच्छे-भले कारण हैं कि उसे वंदे मातरम के संपूर्ण गायन की नई परिपाटी रास नहीं आई। गत दिवस गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह सोनिया गांधी की ओर से कथित तौर पर वंदे मातरम के गायन को रोके जाने पर कांग्रेस से माफी की मांग की, उससे यही लगता है कि कांग्रेस ने जाने-अनजाने भाजपा के हाथ में एक मुद्दा थमा दिया। यह विवाद आसानी से थमने वाला नहीं, इसका संकेत इससे भी मिलता है कि बंकिम चंद्र के वंशज ने भी सोनिया गांधी से माफी की मांग कर दी। वंदे मातरम को लेकर कोई पहली बार विवाद नहीं खड़ा हुआ। इस राष्ट्रीय गीत को लेकर रह-रहकर विवाद का विषय बनाने की कोशिश होती ही रही है। हाल में जब वंदे मातरम के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर मोदी सरकार ने उसके सभी छंद गाए जाने को अनिवार्य बनाया तब भी कांग्रेस ने उस पर आपत्ति जताई थी। इसके उपरांत जब राष्ट्रगान जन-गण-मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देने संबंधी विधेयक पर संसद में चर्चा हुई तब भी कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों ने उसमें भाग लेने से इन्कार किया। 15 अगस्त के समारोह में केरल सरकार ने वंदे मातरम के संपूर्ण गायन से इन्कार करके इस विवाद की जो शुरूआत की, उसे कांग्रेस मुख्यालय में हुए घटनाक्रम ने पूरा कर दिया। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर आयोजित समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने हिस्सा लेने से किनारा किया। उन्होंने ऐसा दूसरी बार किया। यह समझ आता है कि कांग्रेस को मोदी सरकार की रीति-नीति पसंद नहीं, लेकिन सरकार की रीति-नीति और राष्ट्रीय प्रतीकों में अंतर होता है। कांग्रेस एवं अन्य विपक्षी दलों की ओर से प्रायः इस अंतर को भुला दिया जाता है। इससे राष्ट्रीय प्रतीकों के साथ-साथ राष्ट्रीयता की भावना का भी अनादर होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस कांग्रेस ने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया और जिसने अपने अधिवेशनों में वंदे मातरम के गायन की परंपरा प्रारंभ की, वही उसे यथोचित सम्मान देने के लिए तैयार नहीं दिख रही है। मुस्लिम लीग के विरोध के बाद वंदे मातरम के संपूर्ण गायन की जगह उसके दो छंद ही गाने की परंपरा शुरू हुई थी, लेकिन अब इस परंपरा को बदल कर वंदे मातरम के सभी छंद गाए जाने का नियम बनाने पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह आपत्ति किसी न किसी स्तर पर मुस्लिम लीग वाली मानसिकता को पोषण देने वाली ही है।

भारतीय ज्ञान परंपरा को मिली महत्ता

भारतीय ज्ञान परंपरा पर अध्ययन, अध्यापन और शोध की प्रक्रिया भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रारंभ हो गई है। कई विश्वविद्यालयों में इस विषय पर अध्ययन केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं और उच्च शिक्षण संस्थानों में क्रेडिट आधारित पाठ्यक्रम भी बनाए जा रहे हैं। यह पहल हमें अपने सोच, विचार और मानसिकता में विद्यमान औपनिवेशिक प्रभावों से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी। अपनी ज्ञान परंपरा की खोज न केवल औपनिवेशिक शासन में रहे देशों में हो रही है, बल्कि चीन, जापान जैसे कई देश भी अपने राष्ट्रीय स्व को ज्ञान से जोड़ते हुए अपनी जड़, जमीन और संस्कृति में उपजे ज्ञान, मेधा, दक्षता और तकनीकी को अपनी आधुनिकता में शामिल कर रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध, अध्ययन और अध्यापन की प्रक्रिया भारत में विलंब से शुरू हुई है। इसे आजादी के बाद से ही आरंभ हो जाना चाहिए था, लेकिन यह संतोषजनक है कि शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की देखरेख में यह प्रक्रिया अब लगातार आगे बढ़ रही है। इस प्रक्रिया में कुछ चुनौतियां भी हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा मात्र कोई विषय न होकर एक ऐसा दृष्टिकोण है, जिससे हम अपने सभी विषयों और ज्ञान की अनुषंगी इकाइयों को समझ सकते हैं। यह एक दार्शनिक और सैद्धांतिक आयाम रचने के साथ ही अनुभवजन्य और प्रयोगसिद्ध प्रमाणों से भरे ज्ञान की उपयोगिता भी रखता है। इसमें उदाहरण और अनुभव भी शामिल हैं, जो हमारे पाठ्यक्रमों में आ रहे हैं। इसे केवल एक विषय के रूप में देखने की ग्रंथि से हमें मुक्त होना होगा। भारतीय शिक्षा और विमर्श जगत की दूसरी समस्या यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोध और संकलन के क्षेत्र में अभी कम काम हुआ है, जिसके कारण हमारे पास अध्ययन सामग्री का अभाव है। इस कमी को समझते हुए विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान अपने-अपने तरीके से इस दिशा में कार्यरत हैं। समाज विज्ञान से जुड़े शिक्षा संस्थानों में भारतीय समाज के ज्ञान, मेधा, तकनीकी पर शोध, संकलन और अध्ययन सामग्री बनाने का कार्य अभी पर्याप्त गुणात्मकता के साथ प्रारंभ हुआ है। अनेक

विद्वान और समाजशास्त्री इस दिशा में कार्यरत हैं। इन शोधों का परिणाम शीघ्र ही दिखेगा। टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान ने पाठ्यपुस्तक निर्माण की प्रक्रिया में भारतीय ज्ञान परंपरा पर केंद्रित पाठ्यपुस्तकें बनाने के अभियान को खासा महत्व दिया है। अन्य विश्वविद्यालयों को भी भारतीय ज्ञान परंपरा पर ज्ञान सृजन की परियोजना पर काम करना होगा। शिक्षा मंत्रालय में भारतीय ज्ञान परंपरा पर ज्ञान सृजन की प्रक्रिया को सहयोग देने के लिए एक उपखंड भी बनाया गया है, जो ऐसी परियोजनाओं को आर्थिक और दक्षता निर्माण में सहयोग करता है। भारतीय ज्ञान परंपरा की पुनः खोज और उसे शोध एवं शिक्षण से जोड़ने की इस परियोजना की एक बड़ी समस्या इसके अर्थ का गलत पाठ और अनेक वृत्तांतात्मक उलझावों एवं अफवाहपूर्ण अवधारणाओं से गुजरना है। इस संदर्भ में पहली चुनौती इसके अर्थ एवं तत्व मीमांसा की है। भारतीय ज्ञान परंपरा वस्तुतः भारतीय समाज और उसके मिट्टी-पानी और सांस्कृतिक पर्यावरण में उपजा ज्ञान है। यह किसी एक जाति, पंथ और संस्कृति में सृजित एवं विकसित हुआ ज्ञान नहीं है, बल्कि यह उन सभी घटकों के सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव का ज्ञान समुच्चय है, जिनसे भारतीय समाज बनता है। यह बहुलतावादी सामाजिक संस्कृति से उभरा ज्ञान है। यह भारतीय जमीन और पर्यावरण में पले-बढ़े हर संस्कृति के अनुभवों से उपजा ज्ञान है। अतः इसे किसी एक जाति, पंथ और संस्कृति में सीमित करना इसके तात्विक अर्थ का गलत पाठ करना है। हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसी कोटियों से परे यह हर समुदाय, समाज एवं संस्कृति के लौकिक एवं दार्शनिक ज्ञान पर शोध-अध्ययन की हमें छूट देता है। एक तरफ वाल्मीकि, भरतमुनि, वेदव्यास, चरक, सुश्रुत, पतंजलि, कौटिल्य का ज्ञान लोक भारतीय ज्ञान परंपरा का हिस्सा है, दूसरी तरफ बुद्ध, नागार्जुन, भर्तृहरि, कबीर, नानक, रविदास के आख्यान इस ज्ञान विमर्श को रचते हैं। साथ ही अमीर खुसरो, दारा शिकोह तथा अन्य सूफियों का ज्ञान एवं योगियों का विमर्श भी इसमें शामिल है। तात्पर्य यह है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में सीमांत पर बसे समुदायों, दलित, वंचित का ज्ञान अनुभव शामिल है, साथ ही अनेक धार्मिक-सांस्कृतिक समूहों के अनुभव भी इसमें शामिल हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा का परिप्रेक्ष्य समाज की हर सामाजिक इकाई को एक सांस्कृतिक इकाई मानता है, जो अपने दैनंदिन जीवन के अनुभवों के बीच सांस्कृतिक, सभ्यतिक और आध्यात्मिक ज्ञान सृजित करता है। भारत में हर सामाजिक इकाई का एक लोक-जीवन होता है, जिसके अपने गीत, संगीत, सबद, भजन, कीर्तन, कव्वाली, मुहावरे, मसले होते हैं, जिनमें उन सामाजिक समूहों का ज्ञान, विवेक, तकनीकी, दक्षता और नीतियां भरी होती हैं। आवश्यकता है भारतीय लोक ज्ञान के इन सभी रूपों का व्यापक संकलन एवं शोध कर उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा के विविध रूपों को समझने एवं समझाने के लिए उपयोग किया जाए। इसमें स्त्री-पुरुष केंद्रित ज्ञान के साथ ही भारतीय समाज के हर चर-अचर के ज्ञानानुभव संग्रहित हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के इन रूपों में दर्शन, राजनीतिशास्त्र, आर्थिकी, धार्मिक, तकनीकी, चिकित्सकीय, लोक-व्यवहार के भारतीय संस्करण का विशाल भंडार है। इन्हें संकलित कर उनकी व्याख्या और पुनः पाठ करने की आवश्यकता है। हमें इनका आर्काइव विकसित कर उन पर शोध करना होगा और उन शोधों को पाठ्यक्रम में लाना होगा। साथ ही, इन पर उच्च कोटि की पाठ्यपुस्तकें भी विकसित करनी होंगी। भारतीय ज्ञान परंपरा में निहित भारतीयता की व्यापकता एवं बहुलता के ज्ञान, नीतिगत, सांस्कृतिक एवं सभ्यतिक पक्षों पर शोध और अध्ययन करना होगा। इससे हमें अपने भारत को पुनःअविष्कृत करने में मदद मिलेगी। ज्ञान की यह पुनःखोज हमें स्वयं को औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्त करने के साथ ही विकसित भारत के लिए ज्ञान-लोक गढ़ने की भी निमित्त बनेगी।

प्यूपिल्स टाइम्स विशेष शोध-श्रृंखला

2026 का छात्र-आंदोलन : कक्षा से संसद तक

स्वायत्तता से विस्तार तक-जब कक्षा का प्रश्न संसद तक पहुँचा

भाग-4 (खण्ड-1)

किसी आंदोलन का जन्म उसके मूल प्रश्न से होता है, पर उसकी पहचान इस बात से बनती है कि वह समाज के कितने हिस्से को जोड़ पाता है।

अध्याय-1 में हमने उस बेचैनी को समझा जिससे 2026 का आंदोलन जन्मा, अध्याय-2 में उसके सामाजिक आधार और डिजिटल नेटवर्क को देखा और अध्याय-3 में उसे भारतीय छात्र आंदोलनों की निरंतरता में रखा। वहाँ एक बात स्पष्ट हुई-यह आंदोलन प्रारंभ में किसी नेता या दल के इर्द-गिर्द नहीं, बल्कि परीक्षा की विश्वसनीयता, प्रक्रियात्मक न्याय और संस्थागत पारदर्शिता के प्रश्न पर संगठित हुआ। पर इतिहास में कोई आंदोलन देर तक अपने प्रारंभिक दायरे में स्थिर नहीं रहता। जब मांग अध्ययन-कक्ष से निकलकर सार्वजनिक होती है, तब अभिभावक, शिक्षक, नागरिक संगठन, मीडिया और अंततः राजनीतिक दल भी जुड़ते हैं। यहीं से प्रकृति जटिल होने लगती है। 2026 का आंदोलन भी पुस्तकालय से सड़क, सड़क से मीडिया और मीडिया से संसद तक इसी प्रक्रिया से गुजरा। यह विस्तार स्वाभाविक है, प्रश्न यह है कि विस्तार के बाद मूल पहचान कितनी स्पष्ट रहती है। यही इस अध्याय का केंद्र है।

जब परीक्षा का प्रश्न, परिवार का प्रश्न बना

प्रारंभ में मांग स्पष्ट थी। विद्यार्थी सत्ता-परिवर्तन नहीं, यह जानना चाहता था कि परीक्षा कैसे हुई, परिणाम किस पद्धति से तय हुए और त्रुटि की जिम्मेदारी किसकी है। उसके पीछे एक वर्ष की तैयारी, परिवार का आर्थिक निवेश और भविष्य की आकांक्षा थी। इसलिए तकनीकी प्रश्न "परीक्षा कैसे हुई?" धीरे-धीरे सामाजिक प्रश्न "क्या हमारे बच्चों को न्यायपूर्ण अवसर मिल रहा है?" में बदल गया। यहीं से आंदोलन की सामाजिक शक्ति बढ़ी।

स्वायत्तता : आंदोलन की सबसे बड़ी पूँजी

किसी भी आंदोलन की प्रारंभिक स्वायत्तता उसकी सबसे बड़ी पूँजी है। 2026 के शुरूआती चरण में भाषा तकनीकी और प्रशासनिक थी-प्रक्रिया की जानकारी, दस्तावेज, स्पष्टीकरण और प्रभावी शिकायत-व्यवस्था की मांग। वह व्यवस्था को समाप्त नहीं, विश्वास-योग्य बनाने की मांग कर रहा था। संस्था के निर्णय

से असहमति और संस्था की वैधता को नकारना दो अलग बातें हैं। प्रारंभ में असहमति संचालन से थी, वैधता से नहीं, इसलिए व्यापक सहानुभूति मिली। चुनौती तब आई जब दृश्यता बढ़ने पर प्रश्न उठा-क्या विस्तार मूल प्रश्न को मजबूत करेगा या धुंधला?

20 जुलाई : वह मोड़ जिसने दिशा बदल दी

20 जुलाई का घटनाक्रम निर्णायक मोड़ बना। दिल्ली के जंतर-मंतर से संसद की ओर मार्च के प्रयास में प्रदर्शनकारियों और पुलिस में टकराव हुआ। बल-प्रयोग और आँसू गैस के आरोप लगे, पुलिस ने पथराव और बैरिकेड तोड़ने का उल्लेख किया। महत्व टकराव का नहीं, प्रश्न के विस्तार का था। अब तक प्रश्न था "परीक्षा में क्या हुआ?" नया प्रश्न जुड़ा "विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ?" और तीसरा उभरा "लोकतांत्रिक असहमति और सार्वजनिक व्यवस्था में संतुलन की सीमा क्या हो?" यहीं से परीक्षा-सुधार का आंदोलन नागरिक अधिकार और पुलिस-प्रशासनिक उत्तरदायित्व के विमर्श से जुड़ा।

प्रतिनिधित्व बनाम स्वामित्व : राजनीति आई तो क्या बदला?

लोकतंत्र में जब प्रश्न व्यापक हो तो दलों का जुड़ना अस्वाभाविक नहीं। पर प्रतिनिधित्व और स्वामित्व में अंतर है। दल मांग को संसद में उठाए, सरकार से उत्तर मांगे तो वह प्रतिनिधित्व है। पर जब पहचान मूल मांगों के बजाय दलों की उपस्थिति से तय होने लगे तो फोकस-शिफ्ट की चुनौती आती है। 2026 में कांग्रेस, सपा, आप सहित विपक्ष ने मुद्दे को प्रमुखता दी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा सहित नेताओं की सक्रियता ने राष्ट्रीय दृश्यता दी। 22 जुलाई को संसद परिसर के बाहर विपक्षी प्रदर्शन ने NEET विवाद और पुलिस कार्रवाई को जवाबदेही से जोड़ा। महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं कि कौन सही-गलत, बल्कि यह कि क्या राजनीतिक दृश्यता ने मूल प्रश्न को शक्तिशाली बनाया या उसे व्यापक संघर्ष का हिस्सा बना दिया?

...जारी

प्यूपिल्स टाइम्स

रोजगार या ऑटो-रिक्शा परमिट के लिए

'मराठी अनिवार्य' नियम थोपना अनुचित है : रामदास आठवले

मुंबईः केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एक बार फिर रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए 'मराठी अनिवार्य' करने के फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि किसी गरीब कामगार की रोजी-रोटी सिर्फ इसलिए छीन लेना या उसे परेशान करना क्योंकि उसे स्थानीय भाषा पूरी तरह नहीं आती, मुंबई की मूल भावना के खिलाफ है। रामदास आठवले ने कहा, "मुझे मराठी भाषा पर बहुत गर्व है और मेरा दृढ़ता से मानना है कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर व्यक्ति को मराठी जरूर सीखनी चाहिए, क्योंकि यह इस राज्य की आत्मा और हमारी समृद्ध संस्कृति का प्रतीक है। लेकिन इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि मुंबई सिर्फ एक राज्य की राजधानी नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक राजधानी और एक तेजी से उभरता हुआ वैश्विक शहर है।" उन्होंने कहा कि मुंबई में सिर्फ देश के अलग-अलग कोनों से ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया से लोग अपने सपने, रोजगार और उम्मीदें लेकर आते हैं।

मुंबई की असली पहचान और इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी विविधता और हर किसी को खुले दिल से अपनाने की क्षमता में बसी है। आठवले ने कहा, "वैश्विक और समावेशी वास्तविकता को देखते हुए रोजगार या ऑटो-रिक्शा परमिट के लिए 'मराठी अनिवार्य' करने जैसे सख्त कानून थोपना अनुचित लगता है। किसी गरीब कामगार की रोजी-रोटी सिर्फ इसलिए छीन लेना या उसे परेशान करना, क्योंकि उसे स्थानीय भाषा पूरी तरह नहीं आती, मुंबई की मूल भावना के खिलाफ है।" उन्होंने कहा कि हमें अपनी भाषा का सम्मान और प्रचार-प्रसार जरूर करना चाहिए, लेकिन इसे रोजगार की शर्त या सजा बनाकर नहीं। भाषा हमेशा लोगों को जोड़ने का माध्यम होनी चाहिए, विभाजन का नहीं, ताकि मुंबई बिना किसी भाषाई भेदभाव के भारत की धड़कन बनकर आगे बढ़ती रहे। बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम-1988 के तहत महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम-2026 को लागू करने के लिए आधिकारिक शासनादेश जारी किया। संशोधित नियमों के तहत जिन चालकों के पास मराठी बोलने का व्यावहारिक कौशल या कामकाजी ज्ञान नहीं होगा, उन्हें पहले एक महीने का नोटिस दिया जाएगा। अगर चालक एक महीने के भीतर मराठी सीखने में असफल रहता है तो उसके लाइसेंस का प्राधिकरण तीन महीने तक के लिए निलंबित किया जा सकता है। निलंबन के बाद भी नियमों का पालन नहीं करने पर ड्राइविंग लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किया जा सकता है।

मेट्रो अब वसई-विरार तक दौड़ेगी

■ लोकल ट्रेनों का बोझ घटेगा ■ मीरा रोड से विरार तक यात्रियों को मिलेगी राहत

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने मीरा-भाईंदर से वसई-विरार तक मेट्रो-13 को मंजूरी दे दी है। इसके शुरू होने से मीरा रोड, नायगांव, वसई, नालासोपारा और विरार के यात्रियों को लोकल ट्रेनों के अलावा तेज सार्वजनिक परिवहन का विकल्प मिलेगा। इससे रोजाना लोकल से सफर करने वाले यात्रियों का एक हिस्सा मेट्रो की ओर जा सकेगा और पश्चिमी रेलवे की लोकल ट्रेनों पर यात्रियों का बोझ घटने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी की बैठक में लिए गए इन फैसलों से लोकल ट्रेनों पर बना अत्यधिक दबाव काफी हद तक कम होगा। मेट्रो-13 को नायगांव, नालासोपारा और विरार के उपनगरीय रेलवे स्टेशनों से जोड़ा जाएगा। इससे वसई, विरार और नालासोपारा जैसे उपनगरीय इलाकों के यात्रियों की आवाजाही आसान होगी। यात्री लोकल से उतरकर मेट्रो और मेट्रो से लोकल में आसानी से सफर कर सकेंगे। इस मार्ग की मेट्रो-9 से भी कनेक्टिविटी प्रस्तावित है। सभी स्टेशनों पर बस सेवा उपलब्ध कराने की योजना है। इससे यात्रियों को घर से स्टेशन और आगे गंतव्य तक पहुंचने में सुविधा होगी।

रोजाना 4.49 लाख यात्रियों का अनुमान

■ मेट्रो-13 की कुल लंबाई 25.03 किलोमीटर होगी। इसमें 21.78 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड और 3.25 किलोमीटर भूमिगत होगा। मार्ग पर 16 स्टेशन प्रस्तावित हैं। वर्ष 2031 तक रोजाना करीब 4.49 लाख यात्रियों के इस मेट्रो से सफर करने का अनुमान है। सड़क से यात्रा करने की तुलना में समय करीब 50 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है।

17,725 करोड़ रुपए की परियोजना

■ मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी एमएमआरडीए इस परियोजना को तैयार करेगा। इसकी अनुमानित लागत 17,724.99 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने अगले छह महीने में भूमि अधिग्रहण और पहुंच मार्ग तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

मुंबई में मलेरिया, डेंगू, लेप्टो के मरीजों की संख्या बढ़ी

गौरव सिंह/प्यूपिल्स टाइम्स

मुंबईः मुंबई में मॉनसून के दौरान होने वाली एपिडेमिक बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। जून से 15 अगस्त तक मलेरिया के 3177, डेंगू के 1079 और लेप्टो के 189 मामले दर्ज किए गए हैं। इस बीच, 5 लाख 63 हजार 382 लोगों का सर्वे किया गया है। 32 हजार 158 लोगों के ब्लड सैंपल टेस्टिंग के लिए लैब में भेजे गए हैं। पिछले साल इसी समय में मलेरिया के 2852 मरीज थे। इस साल यह संख्या 3177 तक पहुंच गई है। यानी, साल भर में मलेरिया के मरीजों की संख्या बढ़ी है। दूसरी ओर, लेप्टोस्पायरोसिस के मरीज पिछले साल 322 थे, जबकि इस साल 189 हैं। हालांकि, नगर निगम ने लोगों से खास ध्यान रखने की अपील की है क्योंकि मॉनसून के दौरान जमा हुए गंदे पानी के संपर्क में आने से इस बीमारी का खतरा बना रहता है। इस साल पिछले साल के मुकाबले डेंगू के मरीजों की संख्या में कमी आई है। पिछले साल जून-जुलाई-अगस्त 15 तक 1217 मरीज थे, जबकि इस साल 1,079 मरीज रजिस्टर हुए हालांकि, डेंगू मच्छरों की ब्रीडिंग को रोकने की बड़ी चुनौती बनी हुई है। नगर निगम ने 4 लाख 74 हजार 341 ब्रीडिंग जगहों की जांच की, जिनमें से 11,227 जगहों पर एडीज मच्छर ब्रीडिंग करते पाए गए। इसके अलावा, छतों और जगहों से 674 टायर और 25,860 कबाड़ की चीजें हटाई गई हैं। नगर निगम ने 1 से 15 अगस्त के बीच 5 लाख 63 हजार 382 घरों का सर्वे किया है। साथ ही, उनमें से 26 लाख 85 हजार 828 नागरिकों की जांच की गई। इस कैंपेन में 32 हजार 158 ब्लड सैंपल इकट्ठा किए गए। मलेरिया कंट्रोल टीम ने 17,793 ब्रीडिंग जगहों जैसे कुएं, पानी की टंकियां, स्विमिंग पूल वगैरह की जांच की। जिनमें से 3,319 जगहों पर एनोफिलीज मच्छरों का सोर्स मिला। वहीं, 18,568 बिल्डिंग और 3 लाख 18 हजार 803 झोपड़ियों के आस-पास फ्यूमिगेशन किया गया है।

महाराष्ट्र में 124 नई स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण

शिंदे बोले- घर के पास मिले बेहतर इलाज

मुंबईः महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य में 124 नई स्वास्थ्य संस्थाओं, अस्पतालों और उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं का ऑनलाइन लोकार्पण उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया। इस पहल का उद्देश्य लोगों को उनके घर के नजदीक बेहतर और आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान करीब 2.5 से 3 करोड़ महिलाओं की स्वास्थ्य जांच की गई। जांच के दौरान शुरूआती स्तर पर कैंसर के कई मामलों की पहचान हुई, जिससे समय रहते उपचार शुरू करने में मदद मिली। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर जांच और जागरूकता अभियान को आगे बढ़ाने पर जोर दिया।

मैमोग्राफी वैन से बढ़ेगी कैंसर जांच

राज्य में स्तन कैंसर की शुरूआती पहचान के लिए मैमोग्राफी वैन के माध्यम से जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। सरकार का

लक्ष्य विशेष रूप से उन क्षेत्रों तक स्वास्थ्य जांच सुविधाएं पहुंचाना है, जहां लोगों को बड़े अस्पतालों तक पहुंचने में परेशानी होती है।

ठाणे में 900 बेड का आधुनिक अस्पताल

शिंदे ने बताया कि ठाणे शहर में 900 बिस्तरों वाला आधुनिक सिविल अस्पताल वर्ष के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। इस अस्पताल में 200 बेड का महिला एवं बाल अस्पताल और 200 बेड का सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल शामिल होगा। इसके अलावा एयर एंबुलेंस की सुविधा के लिए हेलिपैड भी बनाया जाएगा।

सिकल सेल और टीबी उन्मूलन पर फोकस

उपमुख्यमंत्री ने सिकल सेल रोग की रोकथाम, टीबी उन्मूलन और मातृ-शिशु स्वास्थ्य को मजबूत करने की जरूरत बताई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

NHM कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के संविदा कर्मचारियों को नियमित सेवा में शामिल करने के लिए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार, इससे महामारी के दौरान सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।

पंतनगर पुलिस की त्वरित कार्रवाई

शराब के नशे में पत्नी की हत्या करने वाली सास समेत 5 आरोपी गिरफ्तार

▶▶ तीन लाख में हुई थी हत्या की सुपारी, नौकरानी के पूरे परिवार ने रची थी साजिश

प्यूपिल्स टाइम्स

मुंबईः पंतनगर पुलिस ने घरेलू झगड़े में बहू की हत्या कर उसे दुर्घटना दिखाने वाली सास और उसकी मदद करने वाले नौकरानी के पूरे परिवार को गिरफ्तार कर एक बड़ी साजिश का पदार्फाश किया है। दिनांक 16/08/2026 की रात घाटकोपर निवासी सपना प्रमोद गंज, 35, की संदिग्ध मौत की सूचना राजावाड़ी अस्पताल से मिली थी।

मृतदेह पर गर्दन पर निशान और सिर से खून देखकर पुलिस को शक हुआ।

जांच में पता चला कि मृतका की सास धनलक्ष्मी गंज ने गुस्से में आकर सिर पटककर हत्या की थी।

गहन पूछताछ और सीसीटीवी व तकनीकी सबूतों के आधार पर पुलिस ने खुलासा किया कि मृतका के दुबई से लौटने के बाद सास ने पूर्व नौकरानी मंगला जाधव और उसके पति, बेटे-बेटी के साथ मिलकर 3 लाख रुपये में हत्या की साजिश रची थी।

दिनांक 16/08 को आरोपियों ने घर में घुसकर पहले मिर्ची पाउडर डाला, फिर ओढ़नी से गला घोंटा और पैरों से कुचलकर हत्या कर दी।

पुलिस आयुक्त देवन भारती के मार्गदर्शन में एसीपी विलास दातीर व सीनियर पीआई लता सुतार की टीम ने मुख्य आरोपी सास को 17/08 को और अन्य 4 आरोपियों को 18/08 को गिरफ्तार किया।

सभी आरोपी फिलहाल पुलिस कस्टडी में हैं। इस सराहनीय काम के लिए पूरी पंतनगर पुलिस टीम की सराहना की गई है।

फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला रक्षा बंधन से लागू होगा धर्म स्वतंत्रता कानून

जबरन धर्मांतरण पर सात साल तक की सजा

मुंबई : महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ने राज्य में महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। गृह विभाग से 17 अगस्त को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार यह कानून 28 अगस्त 2026 से प्रभावी हो जाएगा। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 1(2) के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए इसके लागू होने की तारीख निर्धारित की है। सरकार के अनुसार, इस कानून का उद्देश्य जबरदस्ती, दबाव, धोखे, प्रलोभन या अन्य अवैध तरीकों से कराए जाने वाले धर्म परिवर्तन पर रोक लगाना है। नए प्रावधानों के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने के लिए बल, छल या लालच का सहारा लेता है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है और यह अपराध गैर-जमानती श्रेणी में रखा गया है। कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष 60 दिन पहले आवेदन देना होगा। इसके बाद नियमानुसार प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

कानून में नियम-जो मां का, वहीं बच्चे का धर्म

■ राज्य सरकार के फैसले में सबसे अधिक चर्चा उस प्रावधान को लेकर हो रही है, जिसमें कथित तौर पर धोखे, छल या केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किए गए विवाह के मामलों का उल्लेख किया गया है। ऐसे मामलों में विवाह की वैधता और उससे जुड़े कानूनी प्रभावों पर विशेष प्रावधान रखे गए हैं। जानकारी के अनुसार, अगर विवाह केवल धर्म परिवर्तन के उद्देश्य से किया गया पाया जाता है, तो जन्म लेने वाले बच्चे की धार्मिक पहचान के संबंध में मां के विवाह पूर्व मूल धर्म को आधार माना जाएगा।

धर्म परिवर्तन रोकने की सख्त तैयारी

■ शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कानून का समर्थन करते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य जबरदस्ती, दबाव और लालच के जरिए होने वाले धर्म परिवर्तन को रोकना है। यह कानून रक्षा बंधन के दिन लागू होने जा रहा है और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। निरुपम ने आरोप लगाया कि कुछ मामलों में शादी के नाम पर महिलाओं को बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है और बाद में उन्हें छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा कि कानून का उद्देश्य ऐसी परिस्थितियों में महिलाओं के अधिकारों और उनके मूल धर्म की कानूनी स्थिति की रक्षा करना है। कानून में विवाह से जन्म लेने वाले बच्चों के धर्म से जुड़े प्रावधान शामिल हैं और राज्य सरकार महाराष्ट्र की बेटियों की सुरक्षा के लिए मजबूत कानूनी व्यवस्था बना रही है।

महाराष्ट्र के राज्यपाल ने मुंबई की ऐतिहासिक एशियाटिक सोसाइटी को

₹20 लाख दान देने की घोषणा की

मुंबई : महाराष्ट्र के गवर्नर जिष्णु देव वर्मा ने मुंबई में ऐतिहासिक एशियाटिक सोसाइटी का दौरा किया, इसकी मशहूर लाइब्रेरी देखी और सोपारा से दुर्लभ किताबों, डॉक्यूमेंट्स, मैप्स, सिक्कों और आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स के शानदार कलेक्शन को देखा।इस दौरे के दौरान, गवर्नर ने एशियाटिक सोसाइटी को किताबों के अपने कीमती कलेक्शन के बचाव और संवर्द्धन के लिए ₹20 लाख का दान देने की घोषणा की। गवर्नर ने युवा पीढ़ी को संस्था की ओर आकर्षित करने के लिए और ज्यादा कोशिश करने को कहा। उन्होंने कहा कि एशियाटिक सोसाइटी को सिर्फ. किताबों और ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स का भंडार नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे पढ़ने वालों, रिसर्चर्स और ज्ञान चाहने वालों के लिए एक जीवंत सेंटर के तौर पर विकसित होना चाहिए। संरक्षण के बारे में बोलते हुए, गवर्नर ने कहा कि संरक्षण के काम के लिए सिर्फ.रोजाना के ऑफिस टाइम से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए जुनून, लगन और मकसद की मजबूत भावना की जरूरत होती है। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी द्वारा अपने अनमोल कलेक्शन को बचाने के लिए किए जा रहे काम पर संतोष जताया।

मुंबई मेयर के प्रचार पर 25 लाख रुपए खर्च करने का दावा गलत : बीएमसी

मुंबई: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है, जिनमें दावा किया गया था कि मुंबई मेयर के प्रचार के लिए 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे।

बीएमसी ने आधिकारिक बयान में कहा कि अलग-अलग मीडिया आउटलेट्स में ऐसी खबरें आ रही हैं कि मुंबई मेयर के प्रचार पर 25 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इस मामले से जुड़े तथ्य स्पष्ट किए गए हैं। बयान में कहा गया, "बृहन्मुंबई महानगरपालिका कई सोशल मीडिया चैनल चलाता है। इन प्लेटफॉर्म को मैनेज करने के लिए टेक्निकल मैनपावर की जरूरत होती है। मेयर कार्यालय के सोशल मीडिया को मैनेज करने का खर्च उस एजेंसी के जरिए किया जाता है, जिसे पूरे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए नियुक्त किया गया है।" बीएमसी के मुताबिक, महानगरपालिका के अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संभालने के लिए पहले से ही 'रनटाइम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' को निर्धारित टेंडर प्रक्रिया के तहत नियुक्त किया गया है। यह एजेंसी सोशल मीडिया संचालन के लिए तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध कराती है।

बीएमसी ने बताया कि अगस्त 2026 से जुलाई 2027 तक एक साल की अवधि के लिए इसी एजेंसी को सेवा विस्तार देने का प्रस्ताव स्थायी समिति में पहले ही मंजूर हो चुका है। इसी नियुक्त एजेंसी के जरिए मेयर कार्यालय के सोशल मीडिया हैंडलिंग के लिए भी तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध कराई जा रही है।

बीएमसी ने स्पष्ट किया कि मेयर ने इसके लिए किसी अलग एजेंसी की नियुक्ति या अलग से प्रचार कार्य का निर्देश नहीं दिया है। साथ ही, महानगरपालिका ने मीडिया से अपील की है कि इस मामले में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश न किया जाए।

1933 साइबर शिकायत व्यवस्था के दुरुपयोग की आशंका बढ़ी

झूठी या दुर्भावनापूर्ण शिकायतों से निर्दोष नागरिकों की परेशानी और व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल

मुंबई: साइबर अपराधों पर त्वरित कार्रवाई और पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए स्थापित 1933 साइबर शिकायत व्यवस्था डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माध्यम है। हालांकि, यदि इस व्यवस्था का उपयोग व्यक्तिगत विवाद, बदले की भावना, दबाव बनाने अथवा किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए किया जाए, तो यह गंभीर चिंता का विषय बन जाता है।

साइबर अपराध की शिकायत दर्ज कराना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, लेकिन जानबूझकर झूठी, भ्रामक अथवा तथ्यहीन जानकारी देकर शिकायत करना व्यवस्था के दुरुपयोग की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। ऐसी शिकायतों से न केवल निर्दोष व्यक्ति को परेशानी हो सकती है, बल्कि वास्तविक साइबर अपराधों से पीड़ित लोगों तक सहायता पहुँचाने की प्रक्रिया भी प्रभावित हो सकती है।

व्यक्तिगत विवाद को साइबर शिकायत का रूप देने का आरोप: आपसी विवाद, वित्तीय लेन-देन, सोशल मीडिया पर विवाद अथवा अन्य व्यक्तिगत मामलों को कथित रूप से साइबर अपराध का रूप देकर किसी व्यक्ति पर दबाव बनाने के आरोप समय-समय पर सामने आते रहे हैं। शिकायत के बाद बैंकिंग, डिजिटल भुगतान या अन्य ऑनलाइन गतिविधियों से संबंधित प्रक्रियाओं में परेशानी उत्पन्न होने पर संबंधित व्यक्ति को आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, केवल शिकायत दर्ज हो जाना आरोपों के सत्य सिद्ध होने का प्रमाण नहीं है। प्रत्येक मामले में उपलब्ध दस्तावेजों, डिजिटल साक्ष्यों और संबंधित तथ्यों की निष्पक्ष जांच आवश्यक है।

निर्दोष व्यक्ति की सुरक्षा भी जरूरी: विशेषज्ञों के अनुसार, साइबर शिकायत व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए शिकायतकर्ता की जवाबदेही के साथ-साथ शिकायत की सत्यता की उचित जांच भी आवश्यक है। विशेषकर छोटे कारोबारियों और डिजिटल माध्यम से लेन-देन करने वाले नागरिकों के लिए किसी गलत कार्रवाई का आर्थिक प्रभाव गंभीर हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि उसके विरुद्ध जानबूझकर गलत शिकायत की गई है, तो उसे बैंक रिकॉर्ड, चैट, ई-मेल, लेन-देन का विवरण तथा अन्य संबंधित डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित रखने चाहिए और जांच अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

संपादकीय टिप्पणी : साइबर अपराधों के विरुद्ध मजबूत और त्वरित व्यवस्था आज की आवश्यकता है। लेकिन उसकी विश्वसनीयता तभी बनी रह सकती है, जब वास्तविक पीड़ितों को शीघ्र न्याय मिले और निर्दोष नागरिकों को केवल आरोप के आधार पर अनावश्यक परेशानी न उठानी पड़े।

1933 जैसी व्यवस्था सुरक्षा का माध्यम बने-व्यक्तिगत दबाव या प्रतिशोध का नहीं।

प्यूपिल्स टाइम्स राष्ट्रीय समाचार पत्र
"Journalism with Integrity"
chief editor Anurag Shukla

Result Guarantee Above 90% or Money Back
If U R Not Joining Home Tuitions Then U R Missing Many Things
Mumbai's No.1 Premium Home Tuitions Academy
MUMBAI HOME & PRIVATE TUITIONS
1st to 10th ICSE / CBSE / IB / IGCSE / NIOS / State Boards
XI & XII Sci / Comm. IIT, NEET, MHT-CET
Engg, Degree, Diploma, B.Com, Bsc., BMS, MBA, Gmat, Cat, CET, English Speaking
Rajendra Deshmukh MANAGING DIRECTOR
Any Class Home Tuitions Across Mumbai
Get Admission in MBBS
NEET Qualified / Unqualified Fees 25 Lacs (Inc. Food Acc.)
ADMISSIONS OPEN
Branches : Andheri - Worli - Jogeshwari - Malad - Badar - Borivali - Virar
Thane - Vashi - Nerul - Kharghar - Ambernath - Badlapur
Home Tuitions Benefits
Contact : 902 902 9222 / 80 80 80 34 12 / 8446642380 / 9209128153
https://www.mumbaihometutors.com

PRIME KEYS PROPERTIES
Beyond Dreams
BUY | SELL | RENT
FLATS · SHOPS · BUNGALOWS
LANDS · REDEVELOPMENT
Trusted Property Consultant
Residential & Commercial Deals
Best Market Price Assistance
Contact:
+91 9167378057
Your Dream Property, Our Priority

DR. ZUBER SHAH HOSPITAL & POLYCLINIC
Ambernath (W), Maharashtra
Nursing Home Reg. No.: THN-C274*
FACILITIES AVAILABLE
24x7 Emergency Care - Immediate Critical Support
Diabetology & Advanced Diabetic Care
Fever Treatment (Dengue, Chikungunya, Malaria, Influenza)
Cardiology Checkup & ECG Facility
General Medicine Consultation
Vaccination & Immunization Services
Minor Surgical Procedures
OPD & IPD Care Available
Complete Health Checkups
24 HOURS EMERGENCY SERVICE AVAILABLE
DR. ZUBER S. SHAH
M.B.B.S (Reg. No. 2024020955)
Cert. in Diabetology & Emergency Medicine
+91 9323594085 / 8237304085 | Buvapada, K B Road, Ward No. 2/2, Ambernath West, Thane,
Woolen Chawl OPD : 8:00 pm to 11:30 pm | OPD Amber Care : 8149477110

सेहतमंद बीजों के सेवन का सही तरीका जानें

■ डॉ. आशीष मिश्रा
श्रीराम पॉलिक्लिनिक व आयुर्वेदिक दवाखाना

आजकल स्वस्थ रहने के लिए लोग अपनी डाइट में पंपकिन, चिया, फ्लैक्स, सनफ्लावर और हलीम जैसे बीज शामिल कर रहे हैं। अलसी और तिल भारतीय खानपान का लंबे समय से हिस्सा रहे हैं, जबकि चिया और पंपकिन सीड्स का इस्तेमाल हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ा है। ये बीज फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट, मैग्नीशियम, जिंक और दूसरे पोषक तत्व उपलब्ध करा सकते हैं। हालांकि इन्हें खाने का तरीका इनके स्वाद, पाचन और पोषक तत्वों की उपलब्धता को प्रभावित कर सकता है। सभी बीजों को एक ही तरीके से खाना सही नहीं है। कुछ को पीसना, कुछ को भिगोना और कुछ को हल्का भूनना बेहतर हो सकता है।

पंपकिन सीड्स को हल्का भूनकर खाएं: कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स में प्रोटीन, फाइबर, मैग्नीशियम, जिंक और हेल्दी फैट पाए जाते हैं। इन्हें धीमी आंच पर हल्का भूनकर खाया जा सकता है। इससे बीज कुरकुरे और पचाने में आसान हो सकते हैं। हालांकि इन्हें तेज आंच पर ज्यादा देर तक भूनने से बचना चाहिए। नमक वाले पैकेटबंद बीज लेते समय लेबल जरूर देखें, क्योंकि उनमें सोडियम अधिक हो सकता है।

अलसी को पीसना हो सकता है बेहतर: अलसी के छोटे और कठोर बीज कई बार साबुत ही पाचन तंत्र से बाहर निकल सकते हैं। इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट इन्हें पीसकर खाने की सलाह देती हैं। अलसी के पाउडर को आटे, दही, दलिया या लड्डू में मिलाया जा सकता है। पीसी हुई अलसी को हवा बंद डिब्बे में रखकर फ्रिज में रखना बेहतर है, क्योंकि इसमें मौजूद वसा हवा और गर्मी के संपर्क में जल्दी खराब हो सकती है।

चिया सीड्स को भिगोना जरूरी: चिया सीड्स पानी सोखकर फूल जाते हैं और जेल जैसा रूप ले लेते हैं। इन्हें पानी, दूध या दही में भिगोकर खाना सुविधाजनक और सुरक्षित माना जाता है। तीन से चार घंटे या रातभर भिगोए हुए चिया सीड्स को नाश्ते या स्मूदी में शामिल किया जा सकता है। सूखे चिया बीज अकेले निगलने से बचना चाहिए, विशेषकर निगलने में परेशानी वाले लोगों को। हार्वर्ड के अनुसार, चिया बीज तेजी से तरल सोखते हैं, इसलिए उन्हें पहले भिगोकर या नम खाद्य पदार्थ के साथ लेना उचित है।

तिल का तड़का या पिसा रूप: तिल में कैल्शियम के साथ वसा, प्रोटीन और दूसरे खनिज पाए जाते हैं। इन्हें हल्का भूनकर, तड़के में डालकर या पीसकर चटनी के रूप में खाया जा सकता है। तिल की चटनी और पारंपरिक तिल के लड्डू भी इसके सेवन के सामान्य तरीके हैं। हालांकि हड्डियों की मजबूती के लिए केवल तिल पर निर्भर रहने के बजाय संतुलित आहार, पर्याप्त प्रोटीन, विटामिन डी और व्यायाम भी जरूरी हैं।

हलीम के बीज रातभर भिगोएं: हलीम या अलीव सीड्स को पानी या दूध में रातभर भिगोकर सुबह लिया जा सकता है। इन्हें खीर और लड्डू में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये आयरन सहित कई पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, लेकिन एनीमिया या हीमोग्लोबिन की कमी का इलाज केवल इनके भरोसे नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच और उपचार कराना जरूरी है।

सनफ्लावर सीड्स कच्चे या हल्के भुने: सूरजमुखी के बीज कच्चे अथवा हल्के भुने हुए खाए जा सकते हैं। इनमें विटामिन ई, मैग्नीशियम और असंतृप्त वसा होती है। अमेरिकी राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के अनुसार, लगभग 28 ग्राम सूखे भुने सूरजमुखी बीज करीब 49 प्रतिशत दैनिक विटामिन ई उपलब्ध करा सकते हैं। बीज पौष्टिक हैं, लेकिन कैलोरी भी देते हैं। इसलिए सामान्यतः सीमित मात्रा में अलग-अलग बीज लेना बेहतर है। एलर्जी, पाचन संबंधी बीमारी या रक्त पतला करने वाली दवाएं लेने वाले लोग इन्हें नियमित आहार में शामिल करने से पहले चिकित्सक या योग्य आहार विशेषज्ञ से सलाह लें।

'यह परिशिष्ट किसी एक मत या संप्रदाय का प्रचार नहीं, बल्कि मानवता, नैतिकता, आध्यात्मिकता और सहअस्तित्व के सार्वभौमिक मूल्यों का मंच है।'

'आध्यात्मिक संवाद'

नारली पूर्णिमा पर्व पर्यावरण-संवेदी, सामुदायिक और धार्मिक त्यौहार

■ गौरव सिंह/प्यूपिल्स टाइम्स

नारली पूर्णिमा एक विशेष हिंदू पर्व है जिसे मुख्य रूप से मछुआरा समुदाय (विशेषकर महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में) श्रद्धा और भक्ति से मनाता है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों महत्व है."नारली पूर्णिमा" का शाब्दिक अर्थ है "नारियल चढ़ाने वाली पूर्णिमा।" यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। आपको बता दें कि मछुआरे समुद्र को 'समुद्र देवता' मानते हैं, क्योंकि समुद्र उन्हें आजीविका देते हैं और जीवन निर्वाह का माध्यम हैं। इसलिए इस दिन उनकी सच्चे मन से पूजा-अर्चना करते हैं। श्रावण मास में मूसलधार बारिश और समुद्र की उथल-पुथल के बाद मछुआरे जल यात्रा के लिए अच्छा समय मानते हैं। ऐसे में इस दिन मछुआरे समुद्र से शांत रहने और सुरक्षा प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। मछुआरे नारियल को पवित्र फल मानते हैं। ऐसे में इसे समुद्र में प्रवाहित करने का अर्थ होता है-"हे समुद्र देवता! हमारे जीवन, मछली पकड़ने के कार्य और नाव की यात्रा को शुभ व सुरक्षित बनाए रखिए। यह त्यौहार इस बात का भी प्रतीक है कि अब मानसून समाप्ति की ओर है और मछुआरे फिर से समुद्र में जाकर मछलियां पकड़ सकते हैं। नारली पूर्णिमा पर्व पर्यावरण-संवेदी, सामुदायिक और धार्मिक त्यौहार है, जिसमें प्रकृति, विशेषकर समुद्र के प्रति आभार प्रकट किया जाता है। यह परंपरा और आजीविका के संतुलन का सुंदर उदाहरण है।

- श्रावण मास की पूर्णिमा को प्रातःकाल या दिन में शुभ मुहूर्त में किया जाता है। तटीय क्षेत्रों में यह पूजा समुद्र तट पर की जाती है। इस दिन अगर आप मछुआरे हैं तो नाव की सजावट भी करें और नए वस्त्र पहनें।
- पूजा स्थल को साफ करें और भूमि पर जल का छिड़काव करके शुद्ध करिए। इस दिन दीपक और अगर बत्ती जलाकर समुद्र देवता की उपस्थिति का आह्वान करिए।
- इस दिन नारियल को हल्दी-कुमकुम से पूजिए, फिर उस पर पुष्प अर्पित करें। इसके बाद लाल वस्त्र या मौली बांधनी है।
- हे सागर देव! आप ही हमारे जीवन, आजीविका और समृद्धि के आधार हैं। आपकी कृपा से हमारी नौकाएं सुरक्षित चलें, समुद्र शांत रहे और हमें उत्तम फल प्राप्त हो।
- फिर इसे समुद्र किनारे जाकर नारियल को समुद्र में प्रवाहित करते हैं।

उत्तराखंड का रहस्यमयी मंदिर, जहां दिन में तीन बार बदलता है मां का रूप

उत्तराखंड की मनमोहक वादियों में देवी-देवताओं का वास मिलता है। ऐसा ही अल्मोड़ा जिले में शीतलाखेत के पास प्राचीन और प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां स्याही देवी मंदिर स्थित है। शांत वातावरण और पहाड़ों के बीच स्थित मंदिर एक दिन में तैयार किया गया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार, इस मंदिर में माता की मूर्ति दिन में तीन बार अपना रूप बदलती है। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासनकाल में हुआ था और इसे अल्मोड़ा के राजाओं की कुलदेवी माना जाता है। इस पावन मंदिर का निर्माण कत्यूरी शासनकाल में किया गया था। रमणीय पर्वतीय वातावरण के बीच मां का दर्शन आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुपम एहसास कराता है। अल्मोड़ा जनपद आगमन पर आप भी इस पावन मंदिर के दर्शन अवश्य करें। कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण केवल एक रात में हुआ था। लोककथाओं के अनुसार, स्थानीय लोगों ने मंदिर के लिए ईंटें तैयार की थीं. तेज बारिश के बावजूद वे ईंटें अगली सुबह पकी हुई मिलीं। मंदिर को जोड़ने में चूने या सीमेंट की जगह बेल और गुड़ के मिश्रण का प्रयोग हुआ, जो आज भी लोगों को अचंभित करता है। स्याही देवी को आसपास के 52 गांवों की इष्ट देवी माना जाता है और उत्तराखंड के अनेक परिवार इन्हें अपनी कुलदेवी के रूप में पूजते हैं। यह भी कहा जाता है कि इस मंदिर के बनने से पहले, स्याही देवी की असली मूर्ति लगभग आधा किलोमीटर दूर एक दूसरी पहाड़ी पर स्थापित थी। स्याही देवी को अल्मोड़ा के राजाओं की कुल देवी माना जाता था। इसलिए, राजाओं ने इस जगह पर अपनी देवी के लिए एक नया और बड़ा मंदिर बनवाया। जब मंदिर बन गया, तो रोज की पूजा-पाठ और मंदिर की देखभाल के लिए नेपाल से गुरु गोरखनाथ के वंशजों को यहां लाया गया। आज भी उसी वंश के लोग इस मंदिर की पूजा और व्यवस्था संभालते हैं। यह भी कहा जाता है कि कत्यूरी राजा बहुत अच्छे कारीगर और शिल्पकार थे, लेकिन वे अपना सारा निर्माण काम सिर्फ रात में ही करते थे। इसी वजह से कहा जाता है कि यह मंदिर भी सिर्फ एक ही रात में बना था।

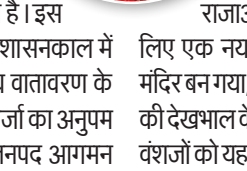

पेज-1 का शेष

भारत और जापान के बीच रक्षा मंत्रियों की बैठक नई दिल्ली में संपन्न...

उन्होंने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है। श्री सिंह ने कहा कि समुद्री मार्गों की सुरक्षा के सामने बढ़ती चुनौतियों के बीच नौवहन की स्वतंत्रता, हवाई क्षेत्र से गुजरने की स्वतंत्रता और वैध व्यापार को बिना बाधा जारी रखना केवल आर्थिक जरूरत नहीं, बल्कि रणनीतिक आवश्यकता भी है। उन्होंने कहा कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की सुरक्षा आपस में गहराई से जुड़ी हुई है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत के महासागर दृष्टिकोण और जापान की स्वतंत्र और खुले हिंद-प्रशांत क्षेत्र की पहल के बीच बेहतर तालमेल आज पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। कोइजुमी ने कुमामोटो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना का आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ-डिफेंस फोर्स के एक जहाज पर चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि यह दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक-दूसरे की मदद कर सकते हैं। जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का उनके दिल में विशेष स्थान है। उन्होंने बताया कि 6 अगस्त 2018 को उन्होंने संसद के अन्य सदस्यों के साथ भारत का दौरा किया था और परमाणु बम के पीड़ितों की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच परियोजनाओं को दी मंजूरी...

ये परियोजनाएं कोयला, लौह अयस्क, सीमेंट, लोहा और इस्पात, कंटेनर, ऑटोमोबाइल और अनाज जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-22 के मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को चार लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि 82 दशमलव 57 किलोमीटर लंबी यह परियोजना तीन हजार 590 करोड़ रुपये से अधिक की कुल पूंजी लागत से विकसित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस परियोजना से यात्रियों और माल की आवाजाही तेज और सुरक्षित होने की उम्मीद है।

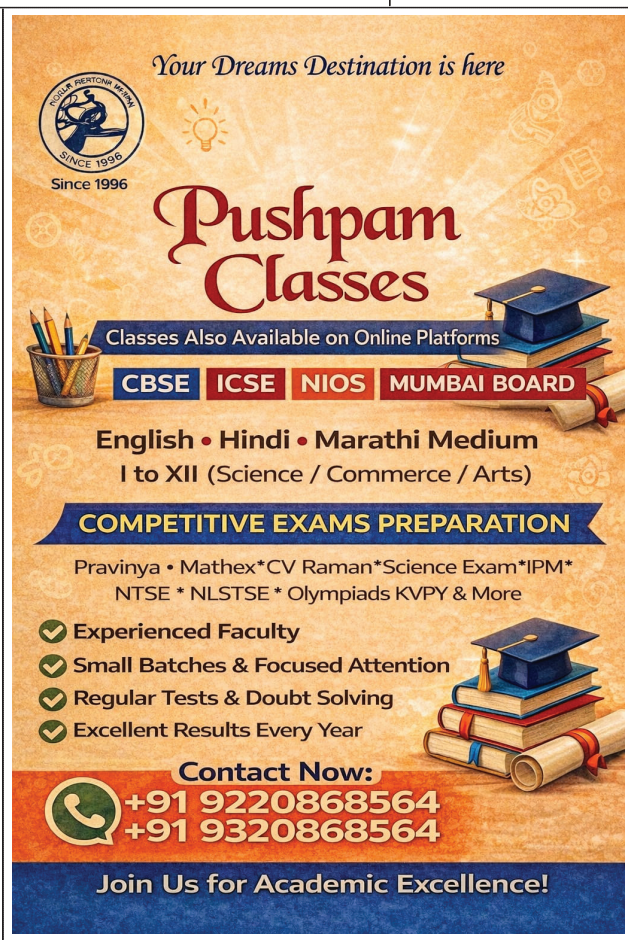

भारत-सिङ्गापुरयोः आर्थिकसम्बन्धेभ्यः नूतना गतिः

पीयूषगोयलस्य नेतृत्वे सप्ततिसदस्यीयस्य भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलस्य सिङ्गापुरयात्रा

प्यूपिल्स टाइम्स/अर्थव्यवस्था-विशेषम्

भारतस्य सिङ्गापुरस्य च मध्ये व्यापार-निवेशसम्बन्धान् अधिकं सुदृढीकर्तुं केन्द्रीय-वाणिज्य-उद्योगमन्त्री पीयूषगोयलः सप्ततिसदस्यीयेन भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमण्डलेन सह सिङ्गापुरं गतवान्। अस्याः यात्रायाः प्रमुखम् उद्देश्यम् उभयोः राष्ट्रयोः मध्ये व्यापारस्य, निवेशस्य, प्रौद्योगिक्याः, नवोन्मेषस्य, बाजारप्रवेशस्य च नूतनानां अवसराणाम् अन्वेषणम् अस्ति। यात्राकाले मन्त्रिस्तरीयाः चर्चाः, व्यापारिकविमर्शाः, उद्योगप्रतिनिधिभिः सह बैठकाः

च भविष्यन्ति। सिङ्गापुरः भारतस्य दक्षिण-पूर्व-एशियायाः प्रमुखेषु आर्थिकसहभागिषु अन्यतमः अस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये व्यापारिकसम्बन्धाः दीर्घकालात् विकसिताः सन्ति। सिङ्गापुरः भारतस्य कृते महत्त्वपूर्णः निवेशस्रोतः अपि अस्ति। अतः परस्परनिवेशस्य विस्तारः, भारतीयव्यवसायानां कृते सिङ्गापुरस्य माध्यमेन वैश्विकविपण्येषु प्रवेशः, आधुनिकप्रौद्योगिक्याः आदान-प्रदानं च आर्थिकसहयोगस्य नूतनानि आयामानि उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति। भारतीय प्रतिनिधिमण्डलेन सह लघु-मध्यम-उद्योगानां, नवोद्यमानां तथा विविधक्षेत्रेषु कार्यरतानां व्यवसायानां सहभागिता अपि महत्त्वपूर्णा भवति। एतेन व्यापारिकसहयोगः केवलं बृहत् उद्योगेषु सीमितः न भूत्वा व्यापकं स्वरूपं प्राप्तुं शक्नोति।

Pupils Times-दृष्टिकोणम् : भारतस्य तीव्रतर-आर्थिकविकासाय वैश्विकनिवेशः, आधुनिकप्रौद्योगिकी, नूतनविपण्येषु प्रवेशः च अत्यावश्यकाः सन्ति। सिङ्गापुरस्य सह सुदृढः आर्थिकसहयोगः 'व्यापारात् विकासः, विकासात् वैश्विकप्रतिस्पर्धा' इति भारतस्य यात्रां अधिकं गतिशीलां कर्तुं शक्नोति।

वचनानां भग्नावशेषेषु निमग्नानि सहस्रशः गृहाणि

पुनर्विकासः समस्यायां परिणतः विकासकानां उपेक्षया प्रशासनिकविलम्बेन च परिवाराणां जीवनम् अस्थिरम्

'विशालतरं गृहं प्राप्स्यथ, आधुनिकाः सुविधाः भविष्यन्ति, जीवनं च सुखमयं भविष्यति।' एतादृशैः आश्वासनैः प्रेरिताः सहस्रशः परिवाराः स्वेषां पुरातनगृहाणि त्यक्त्वा पुनर्विकासस्य मार्गं स्वीकृतवन्तः। जीर्णभवनानां स्थाने नवीनानि उन्नतभवनानि, अधिकं गृहस्थानम्, उत्थापकयन्त्राणि, उद्यानानि अन्याः च आधुनिकसुविधाः भविष्यन्तीति स्वप्नं तेषां पुरतः प्रदर्शितम्। परिवारैः विश्वासः कृतः, गृहाणि रिक्तानि कृतानि, ते च भाटकगृहेषु निवसितुं प्रवृत्ताः। प्रतिज्ञा आसीत्—कतिपयेषु वर्षेषु नवीनानि गृहाणि सज्जानि भविष्यन्ति। किन्तु अनेकपरिवाराणां कृते सा प्रतिज्ञा अद्यापि अपूर्णैव अस्ति। अनेकाः पुनर्विकासपरियोजनाः वर्षाणि यावत् शासकीयानुमतिषु प्रशासनिकप्रक्रियासु च विलम्बिताः अभवन्। यत्र निर्माणकार्यं प्रारब्धम्, तत्रापि अनेकासु परियोजनासु आर्थिकसंकटम्, दुर्बलः परियोजनाप्रबन्धः, विकासकानां च उपेक्षा प्रकाशिता। क्वचित् निर्माणकार्यमध्ये एव स्थगितम्, क्वचित् तु वर्षाणाम् अनन्तरमपि निर्माणकार्ये अपेक्षितः वेगः न दृश्यते। महामारीकाले प्रभावितानां अनेकानां परियोजनानां गतिरपि अपेक्षितसमये पुनः सामान्यतां न प्राप्तवती। सर्वाधिकं पीडादायिनी स्थितिः तेषां परिवाराणां वर्तते, येषां पुरातनगृहेषु निवासः समाप्तः कृत्वा नवीनगृहस्य आशां स्वीकृतवन्तः।

वर्षाणि व्यतीतानि, किन्तु न ते पुरातनगृहेषु प्रत्यागन्तुं शक्नुवन्ति, न च नवीनगृहाणि तेषां हस्तगतानी जातानि। वर्धमानं भाटकभारम्, पुनः पुनः स्थानपरिवर्तनस्य बाध्यता, भविष्यस्य अनिश्चितता च परिवाराणां आर्थिकं मानसिकं च कष्टं वर्धयन्ति। वृद्धानां रोगपीडितानां च कृते एषा स्थितिः अधिकमेव कष्टप्रदा अस्ति। रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरणस्य (RERA) समक्षं, न्यायिकप्रक्रियासु तथा प्रशासनिकस्तरेषु च शिकायताः कृताः सन्ति; तथापि अनेकाः प्रभाविताः परिवाराः अद्यापि समाधानस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति। अधूराणि भवनानि, निर्गतानि लौहदण्डानि, निर्माणस्थलेषु सञ्चितः भग्नावशेषः च तासाम् आशानां कथां कथयन्ति, याः वर्षेभ्यः पूर्णतां प्रतीक्षन्ते।पुनर्विकासस्य उद्देश्यः जनानां जीवनं सुखकरं कर्तुम् आसीत्, न तु तान् वर्षाणि यावत् अनिश्चिततायां स्थापयितुम्। अतः अधुना केवलम् आश्वासनं न, अपितु समयबद्धा उत्तरदायित्वव्यवस्था आवश्यकाऽस्ति। विलम्बितपरियोजनानां स्थितिः सार्वजनिकरूपेण प्रकाशिता भवेत्, उत्तरदायिनां पक्षाणां भूमिका निश्चितीक्रियेत, प्रभावितपरिवारेभ्यः आवश्यकं अन्तरिमसाहाय्यं दीयेत तथा परियोजनाः निर्धारितसमयसीमायां पूर्णाः कर्तुं प्रभावी व्यवस्था क्रियेत। यतः पुनर्विकासस्य अर्थः केवलं पुरातनभवनं पातयित्वा नवीनभवनस्य निर्माणं नास्ति। तस्य वास्तविकः अर्थः अस्ति-पुरातनविश्वासस्य संरक्षणं कृत्वा जनानां नवीनगृहं समये एव समर्पयितुम्। गृहं केवलं चतसृभित्तयः न भवन्ति; तत्प्रत्येकस्य परिवारस्य सुरक्षा, परिचयः, जीवनस्य च आधारः भवति।

क्वाण्टम्-सङ्गणनायाः नूतना प्रगतिः

भविष्यस्य सङ्गणकानां मार्गः सुदृढः

IBM-संस्थायाः मॉड्यूलर-क्रायोजेनिक-प्रौद्योगिक्या अधिकशक्तिशालिनां त्रुटिसहिष्णूनां च क्वाण्टम्-सङ्गणकानां विकासाय नूतना दिशा

प्यूपिल्स टाइम्स/ विज्ञान-प्रौद्योगिकी-विशेषम्

क्वाण्टम्-सङ्गणनायाः क्षेत्रे IBM इत्यनेन एकः महत्त्वपूर्णः तकनीकी-विकासः घोषितः अस्ति। संस्थया प्रथमवारं द्वौ मॉड्यूलर-क्रायोजेनिक-प्रणाली परस्परं संयोज्य, अत्यल्पतापमानयुक्ते वातावरणे सफलतया संचालितौ स्तः। IBM-संस्थायाः अनुसारं, उभे प्रणाल्यौ 15 मिलिकेल्विन इत्यपि न्यूनं तापमानं प्राप्तवन्तौ। क्वाण्टम्-सङ्गणकेषु सूचनायाः मूलभूतः घटकः क्यूबिट् (Qubit) इति कथ्यते। क्यूबिट् अत्यन्तं संवेदनशीलाः भवन्ति। विश्वसनीय-सङ्गणनायै तेषां कृते अत्यल्पतापमानयुक्तं वातावरणम् आवश्यकं भवति। अतः विशालानां क्वाण्टम्-सङ्गणकानां निर्माणे केवलं अधिकानां क्यूबिट्-घटकानां संयोजनं पर्याप्तं नास्ति; तेषां संयोजनाय नियन्त्रणाय च सक्षमं आधारभूत-तन्त्रं आवश्यकम् अस्ति। IBM-संस्थायाः नूतना मॉड्यूलर-व्यवस्था एतस्याः समस्यायाः समाधानस्य दिशि महत्त्वपूर्णं पदम् अस्ति। संस्थायाः अनुसारं, एषा व्यवस्था भविष्ये शताधिकानां क्वाण्टम्-चिप्-घटकानां संयोजनाय विकसितुं शक्यते। IBM-संस्था 2027 तमवर्षपर्यन्तं न्यूनातिन्यूनं 1,000 प्रोग्राम-योग्य-क्यूबिट्-युक्तं विशालं क्वाण्टम्-सङ्गणकतन्त्रं विकसितुं प्रयतते।

अस्याः उपलब्धेः परमं लक्ष्यं त्रुटिसहिष्णु-क्वाण्टम्-सङ्गणनायाः (Fault-Tolerant Quantum Computing) दिशि अग्रसरः भवितुम् अस्ति। क्वाण्टम्-सङ्गणना अद्यापि विकासशीलं क्षेत्रम् अस्ति। तथापि एतादृश्यः प्रगतिः सूचयति यत् भविष्यस्य सङ्गणनं केवलं अधिकवेगयुक्तं न भविष्यति; अपितु जटिलसमस्यानां समाधानस्य मानवीयक्षमतां नूतनां दिशां दातुं शक्नोति।

Dr. Vandana Mishra
M. A. NET (JRF) PHD

दर्पणस्य पारम् : कोऽहम्?

देहात् चेतनायाः प्रति, चेतनायाः आत्मबोधस्य प्रति, आत्मबोधात् जीवात्मनः प्रति यात्रा

दार्शनिकं आध्यात्मिकं च नाटक

दृश्यम्-१ : मोहस्य आवरणम्

[मञ्चे घनम् अन्धकारम्। दूरात् मन्दघण्टाध्वनिः। शनैः प्रकाशः। मध्येऽविशालः दर्पणः। मानवः पुरतः तिष्ठति।]

वाचकः:(गम्भीरया) पश्य। इदं अस्माकं देहम्। मांसम्, रुधिरम्, अस्थीनि, नाड्यः। एतेषां समूहे प्रवहति कश्चित् रहस्यमयः जीवनप्रवाहः। देहः जायते, वर्धते, परिवर्तते, जरां गच्छति, एकदा च विनश्यति। किन्तु किं मनुष्यस्य सम्पूर्णा परिचितिः एतावती एव? न। प्रश्नः देहस्य नास्ति। प्रश्नः तस्य 'अहम्'-भावस्य अस्ति—यः एतां देहं 'मम' इति मन्यते।

मानवः: किन्तु... अहम् कः?

दृश्यम्-२ : त्रयः प्रश्नाः, त्रयः उत्तराणि

[प्रकाशः त्रिधा। एकत्र 'देहः', द्वितीये 'मस्तिष्कम्', तृतीये 'मनः'।]

मानवः: किं अहम् अयं देहः?

देहः: (गम्भीरः) अहं जायामि, वर्धे, जरां गच्छामि, रोगग्रस्तो भवामि, अन्ते च विनश्यामि।

मानवः: यदि त्वं परिवर्तसे तर्हि त्वमेव 'अहम्' कथं भवितुम् अर्हसि?

मानवः: किं अहम् इदं मस्तिष्कम्?

मस्तिष्कम्: (यन्त्रवत्) अहं चिन्तयामि, गणयामि, स्मरामि, विस्मरामि, नूतनं शिक्षामि। किन्तु अहमपि परिवर्ते।

मानवः: तर्हि त्वमपि नित्यः नासि।

मानवः: किं अहं मम विचाराः?

मनः: (चञ्चलः) अद्य प्रसन्नः, श्वः विषण्णः। अद्य प्रेम, श्वः क्रोधः। अद्य इच्छा, श्वः विरक्तिः। अहं क्षणं क्षणं परिवर्ते।

[त्रयः पृष्ठं गच्छन्ति। मानवः एकाकी।]

मानवः: (कम्पितः) यदि देहः परिवर्तते, मस्तिष्कं परिवर्तते, मनः परिवर्तते, विचाराः परिवर्तन्ते तर्हि... कोऽहम्? [मौनम्]

दृश्यम्-३ : द्रष्टुः उदयः

[तमः। एकः प्रकाशकिरणः। तस्मिन् 'अन्तरात्मा'।]

अन्तरात्मा: यत् परिवर्तते तत् त्वं पश्यसि। देहं त्वं पश्यसि, विचारान् जानासि, भावनाः अनुभवसि, इच्छाः निरीक्षसे। किन्तु यः एतानि सर्वाणि पश्यति-सः कः?

मानवः: सः... किं स एव 'अहम्'?

अन्तरात्मा: उत्तरं बहिः मा अन्विष्य। दृष्टिम् अन्तः नय।

वाचकः: अत्रैव प्रारभते अध्यात्मस्य यात्रा। बहिःतः अन्तः। दृश्यात् अदृश्यस्य प्रति। देहात् चेतनायाः प्रति।

दृश्यम्-४ : युद्धं न, जागरणम्

[मनः तीव्रं प्रविशति।]

मनः: तिष्ठ! अध्यात्मस्य मार्गे गन्तुम् इच्छसि? प्रथमं मां जानीहि। अहं तव इच्छा, मोहः, भयम्, क्रोधः, लोभः, अहङ्कारः।

मानवः: (क्रुद्धः) तर्हि त्वां नाशयिष्यामि!

अन्तरात्माः (वारयति) न! अध्यात्मः युद्धं नास्ति। अध्यात्मः जागरणम् अस्ति। क्रोधं न दमनं कुरु-तं जानीहि। लोभात् न पलायस्व-तं पश्य। अहङ्कारं न हन्तव्यम्-तं बोधयित्वा तस्मात् ऊर्ध्वं गच्छ।

मानवः: अर्थात् परिवर्तनम् अन्तः एव आरभते?

अन्तरात्माः आम्। स्वयमेव स्वस्य जयः आत्मविकासस्य प्रथमः सोपानः।

दृश्यम्-५ : अन्तःशुद्धेः सूत्राणि

[प्रकाशः विस्तरति।]

वाचकः: आध्यात्मिकस्य मार्गस्य आधारः न चमत्कारः, न अद्भुतशक्तिः, किन्तु चरित्रस्य परिष्कारः।

अन्तरात्माः शुद्धाः विचाराः स्पष्टां दृष्टिं जनयन्ति। शुद्धाः भावाः करुणां जनयन्ति। संयताः कामनाः आत्मशक्तिं जनयन्ति। सत्यनिष्ठानि कर्माणि साधनां भवन्ति। जागृता चेतना आत्मबोधस्य दिशं दर्शयति।

मानवः: अर्थात अध्यात्मः जीवनात् पृथक नास्ति?

मार्गदर्शकः: (प्रविश्य) न। अध्यात्मः जीवनात् पलायनं नास्ति। अध्यात्मः जीवनस्य परिष्कारः अस्ति। जीवनं सत्यपूर्णं, संयतं, सार्थकं कर्तुम् एषा एव साधना।

दृश्यम्-६ : किम् अध्यात्मः?

मानवः: किं अध्यात्मः चमत्कारदर्शनम्? मार्गदर्शकः: न।

मानवः: अदृश्यलोकानां यात्रा? मार्गदर्शकः:न।

मानवः:असाधारणशक्तीनां प्राप्तिः? मार्गदर्शकः:न।

मानवः: तर्हि किम् अध्यात्मः? [मौनम्। घण्टा]

अन्तरात्माः यदा त्वं स्वस्य अन्तःस्थितम् अन्धकारं पश्यसि प्रकाशं च वृणोषि तदैव अध्यात्मस्य आरम्भः। यदा विचाराः सत्येन, भावनाः करुणया, इच्छाः संयमेन, कर्माणि पवित्रतया पूर्यन्ते। यदा च त्वं 'कोऽहम्?' इति प्रश्नात् न पलायसे अपितु तस्य अन्तः प्रविशसि तदैव अध्यात्मयात्रा प्रारभते।

दृश्यम्-७ : चेतनायाः जीवात्मनः प्रति

[स्वर्णिमः प्रकाशः।]

वाचकः: यदा चेतना जागर्ति तदा प्रश्नः। यदा प्रश्नः गम्भीरः तदा आत्मचिन्तनम्। यदा आत्मचिन्तनं गभीरं तदा आत्मबोधस्य सम्भावना। आत्मबोधः यदा स्वमूलं प्रति मुह्यति तदा यात्रा जीवात्मनः प्रति।

मानवः: मम यात्रा कुत्र आरब्धा? अन्तरात्माः देहात्।

मानवः: अधुना? अन्तरात्माःचेतनायाः प्रति।

मानवः: ततः परम्? मार्गदर्शकः:स्वस्य अन्तर्निहितस्य सत्यस्य अन्वेषणम्। यत् आध्यात्मिकपरम्परासु जीवात्मा इति अनुभूयते।

उपसंहारः : दर्पणस्य पारम्

[मानवः पुनः दर्पणस्य पुरतः। प्रकाशः सर्वतः।]

मानवः: अधुना अस्मिन् दर्पणे न केवलं मम देहं पश्यामि। पश्यामि एकां यात्राम्। देहात् मनसः, मनसः बुद्धेः, बुद्धेः चेतनायाः, चेतनायाः आत्मबोधस्य, आत्मबोधात् च जीवात्मनः प्रति।

वाचकः: मनुष्यस्य जन्मः न सुन्दरतरदेहाय, न तीक्ष्णतरबुद्धये। अपितु स्वस्य सुप्तां चेतनां जागरयितुम्, स्वयं ज्ञातुम्, स्वविचारान् निर्मलान् कर्तुम्, स्वभावनाः करुणामयीः कर्तुम्, स्वेच्छाः संयमयितुम्, स्वकर्माणि सत्यनिष्ठानि कर्तुम्।

अन्तरात्माः यतः अध्यात्मः संसारात् दूरं गन्तुं मार्गः नास्ति। अध्यात्मः स्वस्य सत्यस्य समीपं गन्तुं मार्गः अस्ति।

समापनम् : यात्रा अनवरता

[सर्वे एकपङ्क्तौ।]

मानवः: देहात्... अन्तरात्माःचेतनायाः प्रति।

मार्गदर्शकः: चेतनायाः...

वाचकः: आत्मबोधस्य प्रति।

सर्वेः आत्मबोधात्... जीवात्मनः प्रति।

[मौनम्]

सर्वेः बहिःतः अन्तः, अन्तःतः सत्यस्य प्रति, सत्यात् आत्मबोधस्य प्रति, आत्मबोधात् च अध्यात्मस्य प्रति।

[प्रकाशः केवलं मानवमुखे।]

मानवः: (मन्दम्) अन्वेष्टुं गच्छामि। न जगत्, न नाम, न रूपम्। स्वयम् आत्मानम्।

[घण्टा। प्रकाशः निवर्तते।]

Big step towards 'self-reliant India'

Defense Ministry releases sixth indigenization list of 405 military items

New Delhi: With an aim to promote indigenous production in the defense sector, the Defense Ministry on Tuesday released the sixth Positive Indigenization List (PIL) of 405 strategically important items. These goods are currently being imported and their estimated trade value is Rs 3,070 crore. This list includes line replaceable units, sub-systems, sub-assemblies, spare parts, components and raw materials etc. These include 16 items of the Indian Coast Guard (ICG) and 389 items of Defense Public Sector Undertakings (DPSUs). The items included in this sixth list cover a wide range of defense platforms and systems including advanced light helicopters, light utility helicopters, air platforms like Su-30MKI, light combat aircraft and AL-31FP engines, armored platform warships including T-72, T-90 and BMP-II, missile systems like Konkers-M, Invar

and MRSAM. Are. Along with this are defense electronics including radar, sonar, fire control systems and satellite communication systems, high explosive anti-tank ammunition and other critical defense equipment. An indicative time frame has been given for the indigenization of each of these items. If indigenization is successful, these items will be purchased from the Indian defense industry. According to the Defense Ministry, the sixth positive indigenization list is another step in the government's efforts to promote self-reliance in defense manufacturing under the Atmanirbhar Bharat initiative. This is expected to contribute to expanding opportunities for Indian industry, promoting innovation and reducing dependence on imports. An estimated time frame has been fixed for indigenization of each item, the list of which is available on the Srijan portal of the Defense Ministry. According to the Defense Ministry, after the launch, more than 33000 defense product items have been offered for indigenization through the Srijan portal by June 2026. These include 5,012 items notified under the first five lists of indigenization. Whereas more than 15,700 defense products have been successfully indigenized and this has reduced imports of about Rs 9,000 crore in five years. Apart from this, purchase orders worth about Rs 10,000 crore have been given to domestic defense vendors till March 2026, which also includes indigenous production.

Under the chairmanship of Home Minister Amit Shah

31st Southern Regional Council meeting concluded in Mahabalipuram

Chennai: The 31st South Zone Council meeting concluded in Mahabalipuram near Chennai under the chairmanship of the Home Minister, Amit Shah. The meeting gave an opportunity to the Chief Ministers and Senior Officials to engage among themselves to discuss shared priorities and issues concerning the progress, development and interests of the region.Tamil Nadu Chief Minister Joseph Vijay, Karnataka Chief Minister D.K. Shivakumar, Kerala Chief Minister Satheesan, Telangana Deputy Chief Minister Mallu Bhatti Vikramarka and Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu attended the meeting. Lt Governor of Puducherry, Lt Governor of Andaman and Nicobar Islands, Administrator of Lakshadweep and senior officials of various Ministries also attended the meeting. Meanwhile, the participants during the meeting had stressed upon cooperative federalism across healthcare funding, infrastructure, environmental protection and regional security. While a host of issues were discussed in the closed-door meeting, the participants had expressed satisfaction over the outcome of the meeting on their social media platforms.

Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan stressed on producing agricultural products as per global standards

New Delhi: Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan has said that such agricultural products should be produced in the country, which meet the standards of the global market. He said that for this it is necessary to provide information to the farmers about modern technology and new agricultural equipment. Chouhan was addressing the 97th Annual General Meeting of the Indian Council of Agricultural Research-ICAR in New Delhi. He said that Prime Minister Narendra Modi has called for taking agricultural products from the farm to the global market. Expressing happiness over the progress of Indian agriculture sector, Chauhan said that the annual production of wheat and rice has increased by almost double. He appreciated the contribution of farmers and agricultural scientists in bringing about changes in the agricultural sector. Referring to agricultural reforms, Chouhan stressed the need for climate-friendly seeds. He asked ICAR to conduct research in this direction and take the research forward based on the suggestions received from the states.

Education Minister Pralhad Joshi held a meeting with senior officials on exam reforms

New Delhi: Education Minister Pralhad Joshi held a meeting with the Secretary of Higher Education Department, Director General of National Testing Agency – NTA and other senior officials in New Delhi. During this, Shri Joshi gave instructions to ensure strict adherence to the established examination protocol and to implement comprehensive improvements in the protocols related to confidential operation system, safe rooms, air-gapped systems and storage of electronic equipment on a war footing. He also asked the agency to conduct a comprehensive audit of all examination processes and submit a report on the corrective action taken. In the meeting, the officials briefed him about the steps taken by NTA in view of the recent problems, especially the reforms in the entire examination system. He informed that more

than 50 employees have been removed from NTA. Additionally, advertisements have been issued for 10 new professional leadership positions and the appointment process is underway. Subject experts from the private sector are also being roped in for cyber security, psychometrics, question paper preparation and other specialist areas.

NTA made major changes in the examination system

National Examination Agency has made a major change in the examination system. The agency has decided to remove about 600 experts and include new experts. According to the Education Ministry, a four-tier system will be implemented for checking the question papers. 20 to 25 new officers will also join the agency in the next two to three weeks. Apart from this, security arrangements will be strengthened with the deployment of CISF in the new office of the agency. This decision has been taken on the instructions of Union Education Minister Pralhad Joshi.

Thalapathy Vijay's gift to women

One year's maternity leave will be available even after the birth of the third child

Chennai: Thalapathy Vijay government of Tamil Nadu has given a special gift to women. Female employees will also get 365 days maternity leave on the birth of their third child. At present, married female government employees who have less than 2 living children get 365 days of maternity leave. Those who have two or more living children are entitled to 12 weeks of maternity leave. Human Resource Management Minister D. Sarathkumar gave this information during the discussion on the demand for grants for his department. He said in the Assembly, 'Since the Tamil Nadu government is a welfare administration giving priority to social welfare and

women empowerment. Therefore, the maternity leave currently available to female government employees for the third child will be increased from 12 weeks to 365 days. The then state governments had increased the initial 90 days period of maternity leave to six months in 2011, to 9 months in 2016 and to one year (365 days) in July 2021. A government source said that under the general rules of eligibility, at present this benefit of 365 days of maternity leave is available to those regular female state employees who have less than two living children. However, under the directions of the Supreme Court and subsequent amendments made in the State, female employees of the State Government with two or more living children are also entitled to 12 weeks i.e. 84 days of maternity leave. During this period they will be given full salary. A senior official said that a detailed government order will be issued soon to implement the announcement made in the Assembly. This decision of Thalapathy Vijay government is no less than a gift for women.

Facility to send money home through UPI started for Indians living in Qatar

New Delhi: The service of sending money from Qatar to India based on posttransfer powered by UPI has started. The service allows the Indian community in Qatar to send funds directly to UPI-enabled bank accounts in India through Qatar Post outlets. The Ministry of Communications has said that the service provides a quick, secure, convenient and accessible channel to send money across the border. This will particularly benefit the large Indian community living in Qatar and their families in India. This initiative combines the wide reach of the postal network with India's digital public infrastructure. This should provide an efficient and convenient channel for sending

money across the border. The ministry has said that this service has been developed in collaboration with Qatar Post, India Post, Universal Postal Union's Interconnection Platform-UPU-IP and NPCI International Payments Limited-NIPL.

PUPILS TIMES

Friday, 21 August to 27 August 2026

Indian Army Chief General Dheeraj Seth

Awarded the rank of Honorary General of Nepali Army

New Delhi: Indian Army Chief General Dheeraj Seth has been given the rank of Honorary General of Nepal Army. President Ramchandra Paudel presented him this honor in a ceremony organized at Sheetal Niwas in Kathmandu. Vice President of Nepal Ram Sahay Prasad Yadav, Foreign Minister Shishir Khanal, Indian Ambassador to Nepal Naveen Srivastava and senior officials of Nepal Army and government were present on the occasion. General Dheeraj Seth had reached Nepal on Sunday on the invitation of Nepal Army Chief General Ashok Raj Sigdel. This tradition of conferring honorary posts started in the year 1950. Under this, India and Nepal give the honorary rank of General to each other's army chiefs. General Dheeraj Seth discussed enhancing bilateral military relations with General Sigdel. He also met Ambassador Naveen Srivastava at the Indian Embassy and discussed further strengthening relations between the two countries. He also provided military and medical equipment to the Nepal Army from India.

Clears the way for charging UPI payments

President approved the law

New Delhi: President Draupadi Murmu has approved the legislation related to amendments in the Taxation and Other Laws (Amendment) Act, 2026 and the Payment and Settlement Systems Act, 2007. These bills were passed by Parliament on 10 August. The amendment to the Payment and Settlement Systems Act has given the government the legal basis to impose fees on UPI and RuPay card transactions. The government will be able to decide through notification on which electronic payment means or transactions will not be charged 'Merchant Concessional Rate' (MDR). At present, banks and payment system providers cannot charge users for payments made through UPI and RuPay

debit cards. The UPI and Service Steering Committee headed by NPCI will now take the decision regarding MDR charges. Finance Minister Nirmala Sitharaman had said in the House during the discussion on this bill that UPI payments will remain free for the users and in future the MDR fee will be applicable only on certain categories of business transactions. At the same time, the objective of the Taxation and Other Laws (Amendment) Act is to attract foreign capital, promote domestic electronics manufacturing and facilitate the use of Indian data centers for foreign cloud companies.

Ordinance brought on June 5

This law replaces the ordinance issued on June 5, 2026, under which interest income and capital gains of foreign portfolio investors (FPIs) from investments in government securities were exempted from income tax. In this Act, the income tax exemption available to foreign companies for contract manufacturing of electronics products in India has been extended till the financial year 2040-41. This includes mobile phones, laptops, personal computers, tablets, servers and their major components and accessories.

Big gift to the farmers of UP

Yogi government increased the budget of CM Farmer Accident Welfare Scheme

Lucknow: Farmers and farming are the cornerstone of the state's economy. In such a situation, providing economic and social security to the families associated with farming is one of the priorities of the Yogi government. Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme has emerged as an effective example of this sensitive thinking. The government has continuously given a strong budgetary base to this scheme, which was started to save the farmer and his family from financial crisis in case of an accident. With the provision of crores of rupees, a large number of dependent families getting its benefits, shows the widespread impact of the scheme. Under this, more than 38 thousand dependents have been benefited since the last financial year. Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme is applicable from 14 September 2019. Under the scheme, there is a provision to provide maximum financial assistance of Rs 5 lakh in case of death or disability due to accident. The scope of the scheme has also been kept wide, so that eligible families involved in agricultural work can get government assistance in

difficult times. Along with the account holders and co-account holders registered in Khatauni, such earning family members also come under its purview, whose main source of livelihood is agricultural income from the land registered in the name of the account holder or co-account holders. Eligible landless farmers doing farming on leased or shareholding land can also avail the benefits of the scheme. The continuous increase in its budget also shows the priority of the government. According to the Revenue Department, a provision of Rs 1050 crore was made for the Chief Minister Farmer Accident Welfare Scheme in the financial year 2025-26. The entire amount was allocated as per the demand of the districts and about 21,659 dependent families were benefited from it. This scheme is becoming an effective medium to provide financial assistance to farmer families in times of need. In the financial year 2026-27, the government has further increased the budget for the scheme and made a provision of Rs 1150 crore. That means, compared to the last financial year, the budget has been increased by Rs 100 crore. In relation to this, financial approval of Rs 862.50 crore has been received in the form of first and second installment. As per the demand of the districts, allocation of Rs 813.81 crore has also been made. So far, about 17,152 dependent families have been benefited through this.

Dr. Arvind singh Rana
MBBS, DNB (General Surgery)
General & Laparoscopic Surgeon Coloproctologist
FACRSI, FAMS FIAGES

When an Organ Leaves the Body to Be Saved

The Remarkable Science of Ex Vivo Surgery

What if a diseased organ could be temporarily removed from the body, treated under controlled conditions, and then returned to the patient? What once seemed impossible is now becoming a reality in highly specialized surgical care.

Ex Vivo Surgery is an advanced and highly complex surgical approach in which an organ, or part of an organ, is temporarily removed from the body for treatment and then carefully returned. Ex vivo means "outside the living body." This approach may be considered when a disease is too complex or risky to treat safely while the organ remains inside the body.

One of the most remarkable applications is ex vivo liver surgery. In carefully selected patients with complex liver tumours, conventional surgery may not provide a safe or effective way to remove the disease. In such exceptional cases, surgeons may remove the liver, treat the affected portion outside the body, and then reimplant the organ.

For patients who were once told that treatment options were extremely limited, such advanced techniques can offer a renewed sense of hope.

Keeping the organ viable outside the body is one of the greatest challenges. This is where technologies such as organ perfusion and organ preservation become crucial. Specialized systems can provide the organ with oxygen and essential nutrients, helping maintain its viability while treatment is carried out.

Ex vivo surgery is not a routine procedure and is suitable only for carefully selected patients. It requires highly experienced surgeons, transplant specialists, anesthesiologists, and other professionals working as a coordinated multidisciplinary team, supported by advanced medical facilities.

The significance of ex vivo surgery goes beyond the complexity of the operation itself. It reflects a new philosophy in modern medicine when conventional approaches reach their limits, surgeons can sometimes create an entirely new pathway to preserve an organ and give the patient another chance.

Sometimes, saving an organ may mean taking it out of the body first treating it with extraordinary precision, and then returning it to where it belongs.

That is the remarkable promise of Ex Vivo Surgery: where surgical expertise, advanced technology, and human hope come together to turn some of the most challenging medical situations into new possibilities for life.

PUPILS TIMES
Core Committee

Shivprakash Pandey — Chief Publisher
Vikas Maurya — Co Publisher

Address : Shop No.3, Khatri NX Aprt., Valivali, Badlapur (West) - 421503.
Web : pupilstimes.com

LIC
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
"With you in life, and after life"

भारतीय जीवन बीमा निगम
"ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी"

FREE POLICY CONSULTATION

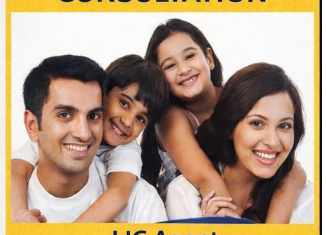

POPULAR LIC PLANS:
- Jeevan Labh — Limited Premium, High Returns
- New Children's Money Back — Secure Your Child's Future
- Jeevan Umang — Whole Life Cover + Pension Benefits
- Bima Jyoti — Guaranteed Additions, Safe Growth
- Also Available – Complete Financial Planning Guidance

KEY BENEFITS:
- Life Insurance + Savings Plan
- Child Education and Marriage Planning
- Retirement Planning
- Tax Benefits Available

LIC Agent
Archana Shukla
+91 91129 39085
+91 74998 67628
Shop No. 2, Near Vithal Mandir, New Vadavali Chowk, Badlapur (West) – 421503
LIC Agent ID: 04497939

ANURAG SHUKLA CHIEF EDITOR . Mob.: +91 9167378057, E-mail: anurag@pupilstimes.com. www.pupilstimes.com

Printes, Published & Owned by : **ANIL MISRA,** Printed at **SOMANI PRINTING PRESS,** UNIT NO. 04, GROUND FLOOR, N. K. INDUSTRIAL ESTATE, OFF. AAREY ROAD, GOREGAON (E.), MUMBAI, MAHARASHTRA - 400064. **Published at :** 94, 1/3 JAI JAWAN VASAHAT, SHIVSHRUSHTI ROAD, KURLA (EAST), MUMBAI - 400024 (MAHARASHTRA). (The editor does not necessarily agree with the news, artical and advertisements published in this issue. Any disputes are subject to the jurisdiction of the Mumbai court) Editor - **ANIL MISRA** , Mob. : 92208 68564, **Email :** anilmisrapc@gmail.com. **PRGI. No. : MHMUL/25/A2419**